भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3524
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

3524. श्री संजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) उठाए गए कदमों के परिणाम क्या हैं; और
(घ) क्षेत्र में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए क्या भावी योजनाएं हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): इस वर्ष के पूवार्द्ध में, वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में, राज्य की सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई है। वास्तविक घुसपैठ में 43 प्रतिशत तथा स्थानीय भर्ती में 40 प्रतिशत की कमी आई है। आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाओं में 28 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बलों द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों को मार गिराए जाने के मामले में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा उपकरण का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कानून का कड़ाई से पालन, घेराबंदी और सर्च अभियानों को बढ़ाने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।

जम्मू और कश्मीर के लोगों के लाभ हेतु समग्र विकास करने के लिए, प्रधानमंत्री ने 80,068 करोड़ रु. के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में सड़क क्षेत्र, विद्युत उत्पादन एवं पारेषण, स्वास्थ्य अवसंरचना, 2 एम्स, आईआईटी एवं आईआईएम की स्थापना और पर्यटन संबंधी परियोजनाओं आदि के रूप में 63 प्रमुख विकास परियोजनाएं शामिल हैं। हिमायत और पीएमकेवीवाई जैसी कई स्कीमों के तहत जम्मू और कश्मीर के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए सीएपीएफ के सिविक एक्शन प्रोग्राम के साथ-साथ वतन को जानो कार्यक्रम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, खेलकूद इत्यादि पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

*****